



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17122021-231899
CG-MH-E-17122021-231899

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 14, 2021/अग्रहायण 23, 1943

No. 647]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 14, 2021/AGRAHAYANA 23, 1943

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: पुणे)

अधिसूचना

पुणे, 7 दिसम्बर, 2021

फा. सं. एक्स1/एसटी/ओएसआर/1325/2021-22.—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद और केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, एतद्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकता है।
(2) इन विनियमों में दिए गए प्रावधान के अनुसार, इन्हें नवंबर, 2012 के पहले दिन से प्रभावी माना जाएगा।
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (इसके उपरान्त एतद्वारा उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित) में, विनियम 3 में, खंड (एफ) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

(एफ) "परिवार" का अर्थ है अधिकारी की पत्नी/ पति, पूर्ण रूप से आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चों और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित), चालीस प्रतिशत या अधिक विकलांगता के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग पूरी तरह से आश्रित भाई या बहन, विधवा बेटियां और आश्रित तलाकशुदा या परित्यक्त बेटियां, बहनें जिनमें अविवाहित या तलाकशुदा या परित्यक्त या पति से अलग या विधवा बहनें शामिल हैं और पूरी तरह से अधिकारी पर निर्भर माता-पिता और विवाहित महिला अधिकारी के मामले में उसके प्राकृतिक माता-पिता या सास-ससुर शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं।

स्पष्टीकरण — "पूर्ण रूप से आश्रित" का अर्थ परिवार के ऐसे सदस्य से होगा जिसकी आय रु.10,000 प्रति माह से अधिक नहीं है और जहां परिवार के पूर्ण आश्रित सदस्य माता-पिता हैं, माता-पिता में से किसी की भी आय या माता-पिता दोनों की कुल आय यदि रु.10,000 प्रति माह से अधिक है तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं माना जाएगा।

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में, उप-विनियम (6) हेतु, निम्नलिखित उप-विनियम सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्: —

“(6) 1 नवंबर, 2012 से प्रभावी प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे :

(क) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VII = रु.76520 – 2120/4 – 85000

वेतनमान VI = रु.68680 – 1960/4 – 76520

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V = रु.59170 – 1650/2 – 62470 – 1800/2 – 66070

वेतनमान IV = रु.50030 – 1460/4 – 55870 – 1650/2 – 59170

(ग) मध्यम प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III = रु.42020 – 1310/5 – 48570 – 1460/2 – 51490

वेतनमान II = रु.31705 – 1145/1 – 32850 – 1310/10 – 45950

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान I = रु.23700 – 980/7 – 30560 – 1145/2 – 32850 – 1310/7 – 42020

स्पष्टीकरण — प्रत्येक अधिकारी, जो 31 अक्टूबर, 2012 को लागू वेतनमानों द्वारा शासित है, को चरण-दर-चरण आधार पर 1 नवंबर, 2012 को इस उप-विनियम के अनुसार निर्धारित वेतनमान में या संबंधित वेतनमानों में पहले चरण से आगे संबंधित चरणों में फिट किया जाएगा और वेतन वृद्धि हमेशा की तरह वर्षगांठ की तारीख पर दी जाएगी।

(7) उप-विनियम (1), (2), (3), (4), (5) और (6) में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में सेवारत अधिकारी आवश्यक हैं।

(8) 1 नवंबर, 2012 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ता दिया जाएगा:

वेतनमान I-III = मूल वेतन का 7.75% + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV-V = मूल वेतन का 10% + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI-VII = मूल वेतन का 11%+ उस पर लागू महंगाई भत्ता

नोट: उप-विनियम (8) में संदर्भित विशेष भत्तों के साथ उस पर लागू महंगाई भत्ते की गणना सेवानिवृत्ति लाभों यथा नई पेंशन योजना, भविष्य निधि और उपदान सहित पेंशन, के लिए नहीं की जाएगी।

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में —

(i) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“(1) विनियम 4 के उप-विनियम (6) के प्रावधानों के अध्यक्षीन, नवंबर, 2012 के पहले दिन को और उस दिन से, वेतन वृद्धि निम्नलिखित के अधीन दी जाएगी, अर्थात् : —

(क) विनियम 4 के उप-विनियम (6) में निर्धारित वेतनमान में निर्दिष्ट वेतन वृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन, वार्षिक आधार पर उपार्जित होगी और उस महीने के पहले दिन दी जाएगी, जिसमें यह देय है;

(ख) अपने संबंधित वेतनमान में अधिकतम स्तर तक पहुंचने के एक वर्ष बाद, वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को अगले उच्च वेतनमान में अवरुद्ध वेतन वृद्धि सहित आगे की वेतन वृद्धि उनके क्षमता मानक को पार करने के अध्यक्षीन नीचे खंड (सी) में निर्दिष्ट अनुसार ही प्रदान की जाएगी;

(ग) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I में अधिकारी, जो उच्च वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के बाद खंड (बी) के संदर्भ में मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II में अंतरित हो गए हैं, सेवा के प्रत्येक तीन पूर्ण वर्षों हेतु चार अवरुद्ध वेतन वृद्धि के पात्र होंगे, जिनमें से पहले दो रु.1310 प्रत्येक और अगले दो रु.1460 प्रत्येक होंगे।

(घ) मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II में अधिकारी, जो उच्च वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के बाद खंड (बी) के संदर्भ में मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में अंतरित हो गए हैं, सेवा के प्रत्येक तीन पूर्ण वर्षों के लिए रु.1460 प्रत्येक की तीन अवरुद्ध वेतन वृद्धि और तीसरी अवरुद्ध वेतन वृद्धि प्राप्त होने के दो वर्ष के उपरांत रु.1460 की चौथी अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि जिन अधिकारियों ने तीसरी अवरुद्ध वेतन वृद्धि की प्राप्ति के बाद दो साल या उससे अधिक की अवधि पूर्ण कर ली है, उन्हें मई, 2015 के पहले दिन से चौथी अवरुद्ध वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी;

(ङ) मूलतः मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में अधिकारी (जो मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में भर्ती या पदोन्नत हुए हैं) सेवा के प्रत्येक तीन पूर्ण वर्षों के लिए रु.1460 प्रत्येक की तीन अवरुद्ध वेतन वृद्धि हेतु और 1 मई, 2015 को तीसरी अवरुद्ध वेतन वृद्धि जारी करने के बाद दो साल या उससे अधिक अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारियों को रु.1460 की चौथी अवरुद्ध वृद्धि और चौथी अवरुद्ध वेतन वृद्धि की प्राप्ति के दो साल बाद रु.1460 की पांचवीं अवरुद्ध वेतन वृद्धि जारी करने के पात्र होंगे बशर्ते कि वे अधिकारी जिन्होंने चौथी अवरुद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त होने के बाद दो साल पूरे कर लिए हों उन्हें 1 मई, 2015 से पांचवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी;

(च) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान - IV के अधिकारी अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के तीन साल बाद 1 मई, 2015 से रु.1650 की एक अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे;

बशर्ते कि ऐसी वेतन वृद्धि की अनुमति किसी ऐसे अधिकारी को नहीं दी जाएगी जो प्रस्ताव दिए जाने पर पदोन्नति से इंकार कर देता है।

स्पष्टीकरण — इस उप-विनियम के अंतर्गत अगले उच्च वेतनमान में इस तरह की वेतन वृद्धि को पदोन्नति के रूप में नहीं माना जाएगा और अधिकारियों के विशेषाधिकार, अनुलाभ, कर्तव्य और उत्तरदायित्व उनके मूल पदों के रूप में जारी रहेंगे।

(ii) उप-विनियम (2) में, स्पष्टीकरण में, खंड (एफ) के उपरांत और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात् —

"(छ) नवंबर, 2012 के पहले दिन को और उस दिन से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतन की मात्रा नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट किए अनुसार संशोधित होगी:

तालिका

(1)	(2)
जिन्होंने जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स - भाग I उत्तीर्ण किया है	रु. 670 प्रति माह, अधिकतम स्केल पर पहुंचने के एक वर्ष उपरांत
जिन्होंने सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हों	(i) रु. 670 प्रति माह, अधिकतम स्केल पर पहुंचने के एक वर्ष उपरांत (ii) रु. 1680 प्रति माह, अधिकतम स्केल पर पहुंचने के दो साल उपरांत

बशर्ते कि वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के उपरांत जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (या तो एक या दोनों भागों) की योग्यता प्राप्त करने वाले अधिकारी को ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त दी जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की अगली किस्तों का जारीकरण व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त जारी करने की तारीख के संदर्भ के साथ होगा";

(iii) उप-विनियम (3) में, खंड (ई) के अंतर्गत तालिका के उपरांत, निम्नलिखित प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ज)" 1 नवंबर, 2012 को और उस दिन से, अन्य बातें समान होने पर, मकान किराया भत्ते (एचआरए) के साथ निश्चित वैयक्तिक वेतन निम्नलिखित दरों पर होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेगा:

तालिका

वेतन वृद्धि घटक (रु.)	वेतन वृद्धि घटकों पर 01.11.2012 को महंगाई भत्ता (रु.)	कुल देय निश्चित वैयक्तिक वेतन (एफपीपी) जहां बैंक का आवास प्रदान किया गया है (रु.)
(1)	(2)	(3)
1310	143	1453
1460	159	1619
1650	180	1830
1800	196	1996
1960	214	2174
2120	231	2351

नोट:

(i) इस उप-विनियम के खंड (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) में तालिकाओं के कॉलम (3) के अंतर्गत दर्शाया गया निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ii) आवास किराया भत्ता हेतु पात्र अधिकारियों के लिए निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन, खंड (एफ) के अंतर्गत तालिका के कॉलम (1) और (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट कुल राशि और संबंधित अधिकारी द्वारा लिया गया आवास किराया भत्ता (एचआरए) होगा जब विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5) और (6) में निर्दिष्ट प्रासंगिक वेतनमान की अंतिम वेतन वृद्धि अर्जित की जाती हो।

(iii) केवल वही अधिकारी जो 1 नवंबर, 1993 को या उससे पहले बैंक की सेवा में थे, जिस वेतनमान में वे हैं, उसके वेतन के अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के एक वर्ष उपरांत निश्चित वैयक्तिक वेतन के लिए पात्र होंगे।

(iv) 1 नवंबर, 1999 को और उस दिन से, निश्चित वैयक्तिक वेतन जारी करने के कारण उप-विनियम (2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण (सी) के अनुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन जारी करने की समय-सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा:

बशर्ते कि जहां व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई किस्त, जो पहले के प्रावधानों के कारण एक वर्ष के लिए अंतरित कर दी गई है और 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी किए जाने के लिए निर्धारित है, वह अधिकारी को उस दिनांक को और उस दिनांक से तथा व्यावसायिक योग्यता वेतन, यदि कोई हो, की दूसरी किस्त 1 नवंबर, 2000 को जारी की जाएगी।

(v) निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन का वृद्धिशील घटक अधिवर्षिता लाभों के लिए रैंक किया जाएगा।

(vi) कोई अधिकारी जिसने इस उप-विनियम के खंड (ए) के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि अर्जित की है, उसे वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के एक वर्ष के उपरांत उपर्युक्त खंड (बी), (सी), (डी), (ई) या (एफ) में उल्लिखित निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन की मात्रा प्राप्त होगी।

5. उक्त विनियमों के विनियम 21 में, उप-विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(6) नवंबर 2012 के पहले दिन को और उस दिन से, अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 वेतन के 0.10% पर तिमाही औसत में 4440 अंकों पर चार अंकों की प्रत्येक वृद्धि या गिरावट के लिए महंगाई भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण - इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, -

- (क) महंगाई भत्ते के उद्देश्य के लिए "वेतन" का अर्थ मूल वेतन होगा जिसमें अवरुद्ध वेतन वृद्धि और विशेष भत्ता शामिल है;
- (ख) विनियम 5 के उप-विनियम (2) में स्पष्टीकरण के लिए खंड (सी), (डी), (ई), (एफ) और (जी) में निर्दिष्ट व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन महंगाई भत्ता के लिए रैंक होगा।"

6. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, —

(i) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1) नवंबर, 2012 के पहले दिन को और उस दिन से, -

- (क) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, वहां उस वेतन के पैमाने के पहले चरण, जिसमें वह पदस्थ है, में मूल वेतन के 0.75 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, उससे वसूल किया जाएगा;
- (ख) जहां अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, वहां वह निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता के लिए पात्र होगा, अर्थात्: -

तालिका

कार्य स्थल	आवास किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) ग्रुप ए में प्रमुख श्रेणी के शहर और "ए" परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 9.0 प्रतिशत
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान और समूह बी में परियोजना क्षेत्र केंद्र तथा गोवा राज्य	वेतन का 8.0 प्रतिशत
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 7.0 प्रतिशत

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है, तो उसे देय मकान किराया भत्ता उसके द्वारा उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित उपरोक्त दरों के अनुसार देय मकान किराया भत्ता के अधिकतम 150 प्रतिशत के साथ वेतनमान, जिसमें वह पदस्थ है, के पहले चरण में वेतन के 0.75 प्रतिशत से अधिक आवासीय सुविधा के लिए भुगतान किया गया वास्तविक किराया होगा।

नोट:- उनके स्वामित्व आवास की लागत से जुड़े मकान किराया भत्ता हेतु अधिकारी के दावे भी अब तक की तरह ही मकान किराया भत्ता के 150 प्रतिशत तक सीमित रहेंगे।

7. उक्त विनियमों के विनियम 23 में, —

(क) उप-विनियम (1), (2), (3), (4), और (5) हेतु, निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) नवंबर, 2012 के पहले दिन को और उस दिन से, यदि कोई अधिकारी नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित स्थान पर सेवा कर रहा है, तो उस स्थान के समक्ष कॉलम (2) में उल्लिखित दर पर एक नगर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा:

तालिका

स्थान	दरें
(1)	(2)
(i) क्षेत्र 1के स्थान और गोवा राज्य	मूल वेतन का 4 प्रतिशत जो अधिकतम रु.870 प्रति माह के अध्यक्षीन है।
(ii) पांच लाख और उससे अधिक की आबादी वाले स्थान तथा राज्य की राजधानियां और चंडीगढ़, पुडुचेरी और पोर्ट ब्लेयर।	मूल वेतन का 3 प्रतिशत जो अधिकतम रु.600 प्रति माह के अध्यक्षीन है।

(2) नवंबर, 2012 के पहले दिन को और उस दिन से, विशेष क्षेत्र भत्ते की दरें इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट किए अनुसार होंगी।

(3) नवंबर, 2012 के पहले दिन को और उस दिन से, यदि कोई अधिकारी समूह ए या समूह बी में पड़ने वाले परियोजना क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सेवारत है, तो वह क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार क्रमशः ग्रुप ए या ग्रुप बी के रूप में प्रति माह रु.400 या प्रति माह रु.350 की दर पर परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र होगा।

(4) जून, 2015 के पहले दिन को और उस दिन से, यदि किसी अधिकारी का शैक्षणिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किया जाता है और यदि उसका एक या उससे अधिक बच्चे पूर्व के स्थान पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वह बाद के दूसरे स्थान पर रिपोर्ट करने के दिनांक से सभी बच्चों के संबंध में शैक्षणिक वर्ष के अंत तक प्रति माह रु.1100 का मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानान्तरण भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा बशर्ते कि यदि सभी बच्चे पूर्व स्थान पर पढ़ना बंद कर दें तो ऐसा भत्ता समाप्त हो जाएगा।

(5) जून, 2015 के पहले दिन को और उस दिन से, यदि कोई अधिकारी बैंक से बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त है, तो वह उस पद, जिस पर वह प्रतिनियुक्त है, से जुड़ी परिलब्धियों को प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, या वह अपने वेतन के अतिरिक्त अधिकतम रु.4000 प्रति माह के अध्यक्षीन अपने वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता जो और ऐसे अन्य भत्ते जो वह उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने पर हासिल करता, प्राप्त कर सकता है:

बशर्ते कि वह ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त है जो उसी स्थान पर स्थित है जहां वह अपनी प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले तैनात था, तो उसे अधिकतम रु.2000 प्रति माह के अध्यक्षीन अपने वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त होगा:

बशर्ते यह भी कि बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्ति पर कोई अधिकारी अधिकतम रु.2000 प्रति माह के अध्यक्षीन अपने वेतन के 4 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।";

(ख) उप-विनियम (8) हेतु, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(8) नवंबर, 2012 के पहले दिन को और उस दिन से, यदि एक दिन के दौरान कार्य घंटों को दो घंटे के न्यूनतम अंतराल के साथ विभाजित किया जाता है, तो एक अधिकारी रु.200 प्रति माह की दर से स्प्लिट ड्यूटी भत्ते के लिए पात्र होगा।";

(ग) उप-विनियम (10) में, -

(क) "नवंबर 2007 का पहला दिन" के अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "नवंबर, 2012 का पहला दिन" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) तालिका के लिए निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले स्थान लेकिन 1500 मीटर से कम और मर्कारा टाउन	अधिकतम रु.750 प्रति माह के अध्यक्षीन वेतन का 2 प्रतिशत

(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक लेकिन 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान	अधिकतम रु.1000 प्रति माह के अध्यक्षीन वेतन का 2.5 प्रतिशत
(iii) 3000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाला स्थान	अधिकतम रु.2000 प्रति माह के अध्यक्षीन वेतन का 5 प्रतिशत

8. उक्त विनियमों के विनियम 24 में,—

(i) उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

"(1) नवंबर, 2012 के पहले दिन को और उस दिन से, एक अधिकारी अपने और परिवार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, जो अधिकारी के स्वयं के प्रमाण पत्र के आधार पर इस तरह के उपचित खर्च के लिए दावा की गई राशि के लिए खातों के विवरण द्वारा समर्थित हो, जैसा कि नीचे तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्:-

तालिका

श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
(1)	(2)
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्यम प्रबंधन श्रेणी	रु.8000 प्रति वर्ष या उपगत की गई राशि जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	रु.9050 प्रति वर्ष या उपगत की गई राशि जो भी कम हो

नोट :

(i) किसी अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता संचित करने की अनुमति दी जा सकती है ताकि यह किसी भी समय ऊपर प्रदान की गई अधिकतम राशि के तीन गुना से अधिक न हो; या

(ii) वर्ष 2012 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति को दो महीनों, यानी नवंबर, 2012 और दिसंबर, 2012 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा।

(1A) एक अधिकारी निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार अपने और अपने परिवार के लिए चिकित्सा बीमा सुविधा के लिए पात्र होगा।"

9. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2) उप-विनियम (1) में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, बैंक के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वह अधिकारी द्वारा भुगतान किए जाने पर नवंबर, 2012 के पहले दिन को और उस दिन से किसी अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगा, जो उस वेतनमान के पहले चरण में मूल वेतन का 0.75 प्रतिशत की राशि के बराबर है जिसमें वह पदस्थ है या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो।

बशर्ते कि जहां अधिकारी को ऐसे आवास पर फर्नीचर प्रदान किया जाता है, वहां बैंक द्वारा उस वेतनमान, जिसमें वह पदस्थ है, के पहले चरण में मूल वेतन के 0.15 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी:

बशर्ते यह भी कि जहां बैंक द्वारा ऐसी आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, वहां बिजली, पानी, गैस और वातावरण संरक्षण (कंजर्वेन्सी) का प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।"

10. उप-विनियम (4) के लिए उक्त विनियमों के विनियम 33 में, निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(4) जून 2015 के पहले दिन को और उस दिन से, विशेषाधिकार अवकाश दो सौ सत्तर दिनों से अधिक जमा नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि छुट्टी के लिए आवेदन किया गया है और इसे अस्वीकार कर दिया गया है:

बशर्ते कि विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम दो सौ चालीस दिनों तक प्रतिबंधित किया जाएगा:

बशर्ते यह भी कि विशेषाधिकार अवकाश का लाभ लेने का इच्छुक अधिकारी सामान्यतया ऐसी छुट्टी लेने के अपने इरादे की कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना देगा।"

11. उक्त विनियमों के विनियम 34 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(4) 1 जून 2015 को और उस दिन से, किडनी या अंग दान के लिए एक अधिकारी को उसकी पूरी सेवा की अवधि के दौरान एक बार तीस दिनों तक का विशेष बीमारी अवकाश दिया जा सकता है।"

12. उप-विनियम (2) और (3) के लिए उक्त विनियमों के विनियम 36 में, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(2) 25 मई 2015 से, एक निःसंतान महिला अधिकारी को एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए सेवा के दौरान एक बार छुट्टी दी जा सकती है, जो निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए है:—

- (i) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए छुट्टी दी जाएगी;
- (ii) एक बच्चे को उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से गोद लेना होगा और अधिकारी ऐसी छुट्टी की मंजूरी के लिए बैंक को दत्तक विलेख प्रस्तुत करेगी;
- (iii) बायोलॉजिकल माँ को भी उन मामलों में छुट्टी उपलब्ध होगी जहां बच्चे का जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ हो; तथा
- (iv) सेवा की सम्पूर्ण अवधि के दौरान छुट्टी, बारह महीने की समग्र पात्रता के भीतर प्राप्त की जाएगी।

(3) मई, 2015 के 25वें दिन से हिस्टेरेक्टॉमी के मामले में, बारह महीने की कुल अवधि के भीतर, अधिकतम साठ दिनों तक की छुट्टी भी दी जा सकती है।

(4) मातृत्व अवकाश, जो मूल वेतन पर होगा, एक महिला अधिकारी को किसी भी एक अवसर पर अधिकतम छह महीने और उसकी सेवा की सम्पूर्ण अवधि के दौरान बारह महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा।

बशर्ते कि बारह माह की अधिकतम अवधि के भीतर गर्भपात या मिस्केरेज या गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के मामले में भी छुट्टी प्रदान की जा सकती है।

(5) 1 जून 2015 से, पुरुष अधिकारी कर्मचारी जिनके अधिकतम दो जीवित संतानें हैं, वे अपनी पत्नी की प्रसूति के दौरान पंद्रह दिनों के पितृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगे, जिसे आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है:

बशर्ते कि छुट्टी बच्चे के जन्म की तारीख से पंद्रह दिन पूर्व या आगामी छह माह तक आवेदित की जाएगी।"

13. उक्त विनियमों के विनियम 38 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"38. छुट्टी की समाप्ति, — नीचे दिए गए प्रावधान के अलावा, किसी अधिकारी के खाते में जमा सभी छुट्टियां इस्तीफे, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवामुक्ति, बर्खास्तगी या टर्मिनेशन होने पर समाप्त हो जाएंगी:

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होता है, तो वह किसी अवधि के लिए परिलब्धियों के समतुल्य राशि के भुगतान हेतु पात्र होगा, जो उसके द्वारा संचित दो सौ चालीस दिनों की विशेषाधिकार छुट्टी से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते यह भी कि यदि किसी अधिकारी को सजा के उपाय सहित अनिवार्य रूप से (कम्पलसरिली) सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, तो वह किसी अवधि के लिए परिलब्धियों के समतुल्य राशि के भुगतान हेतु पात्र होगा, जो उसके द्वारा संचित दो सौ चालीस दिनों की विशेषाधिकार छुट्टी से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि यदि किसी अधिकारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के दिनांक की अवधि तक की परिलब्धियों के समतुल्य राशि का भुगतान उसके विधिक प्रतिनिधियों को किया जाएगा, जो उसके द्वारा संचित दो सौ चालीस दिनों की विशेषाधिकार छुट्टी से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते यह भी कि यदि कोई अधिकारी 1 अप्रैल, 2001 को या उसके उपरांत विनियम 20 के उप-विनियम (2) के अनुसार समुचित नोटिस देने के बाद सेवा से इस्तीफा देता है, तो उसे विशेषाधिकार छुट्टी के संबंध में सेवा की समाप्ति की तिथि को जमा छुट्टियों के आधे भाग तक अधिकतम एक सौ बीस दिनों की अवधि के अध्यक्षीन परिलब्धियों के समतुल्य राशि का भुगतान किया जा सकता है।"

14. उक्त विनियम के विनियम 41 में,—

(i) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1) नवंबर 2012 के पहले दिन को और उसके बाद, यदि किसी अधिकारी को कार्यालयीन कार्य से यात्रा करने की आवश्यकता होती है, तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थात्:—

(क) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी के अधिकारी रेल की प्रथम श्रेणी या एसी 2-टियर स्लीपर से यात्रा करने हेतु पात्र हैं:

बशर्ते कि वह हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय की अत्यावश्यकताओं या सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अनुमति प्रदान की गई हो;

(ख) मध्यम प्रबंधन श्रेणी के अधिकारी रेल की प्रथम श्रेणी या एसी 2-टियर स्लीपर से यात्रा करने हेतु पात्र हैं:

बशर्ते कि वह हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है, यदि यात्रा की जाने वाली दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक हो:

बशर्ते यह भी कि वह कम दूरी के लिए भी हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय की अत्यावश्यकताओं या सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अनुमति प्रदान की गई हो।

(ग) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी के अधिकारी रेल की एसी प्रथम श्रेणी या हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा करने हेतु पात्र हैं;

(घ) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी के अधिकारी हवाई जहाज या रेल से नहीं जुड़े स्थानों के बीच कार से यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते कि दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो:

बशर्ते कि जब दो स्थानों के बीच की दूरी का एक प्रमुख हिस्सा हवाई जहाज या रेल के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, तभी बाकी बची दूरी सामान्यतः कार द्वारा तय की जानी चाहिए;

(ङ) व्यवसाय की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को भी अपने वाहन या टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है;

(च) किसी भी श्रेणी या वेतनमान का अधिकारी सड़क या हवाई जहाज या रेल से नहीं जुड़े स्थानों के बीच यात्रा करने के लिए जल परिवहन के डिलक्स केबिन श्रेणी में यात्रा करने हेतु पात्र होगा।”;

(ii) उप-विनियम (4) में, खंड (ए) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(क) 1 जून, 2015 को और उसके बाद से, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित श्रेणी या वेतनमान के अधिकारी उसके तदनुसारी कॉलम (2) में निर्धारित संबंधित दरों पर दैनिक विराम भत्ते हेतु पात्र होंगे, अर्थात्:—

तालिका

अधिकारियों के श्रेणी / वेतनमान	महानगर (रू.)	प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर (रू.)	क्षेत्र-1 (रू.)	अन्य स्थान (रू.)
(1)	(2)			
वेतनमान VI और उससे वरिष्ठ अधिकारी	1800	1300	1100	950
वेतनमान IV और V के अधिकारी	1500	1300	1100	950
वेतनमान I, II और III के अधिकारी	1300	1100	950	800

बशर्ते कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम लेकिन चार घंटे से अधिक हो, वहां उपर्युक्त दरों का आधा विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण — विराम भत्ता की गणना के लिए, “दैनिक” से तात्पर्य चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसका अनुवर्ती कोई हिस्सा, हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय और अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से आगमन

के वास्तविक समय तक गणना की जाती है और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है वहां, "दैनिक" से तात्पर्य ऐसी अवधि होगा जो आठ घंटों से कम न हो।"

15. उक्त विनियमों के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) हेतु, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(3) जून, 2015 के पहले दिन को और उसके बाद से, स्थानांतरण पर एक अधिकारी निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट अनुसार पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा आदि से जुड़े व्ययों के लिए एकमुश्त राशि पाने हेतु पात्र होगा, अर्थात्:—

तालिका

श्रेणी या वेतनमान	राशि
(1)	(2)
शीर्ष कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी (वेतनमान IV और उससे वरिष्ठ अधिकारी)	रु.20,000
मध्यम प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी (वेतनमान III तक के अधिकारी)	रु.15,000"

16. उक्त विनियमों के विनियम 44 में, उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) चार वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान, एक अधिकारी दो वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार अपने अधिवास स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत हेतु पात्र होगा:

बशर्ते कि, वह दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने अधिवास स्थान और दो वर्ष के दूसरे ब्लॉक में भारत के किसी भी स्थान पर निकटतम मार्ग से यात्रा कर सकता है:

बशर्ते यह भी कि 1 जून 2015 से, वैकल्पिक रूप में, एक अधिकारी, यथा मामला चार वर्ष के ब्लॉक या दो वर्ष के ब्लॉक के दौरान किसी भी समय एक विकल्प का प्रयोग करके अपनी छुट्टी यात्रा रियायत (अधिवास के स्थान की यात्रा के अलावा) का समर्पण कर और यात्रा की अपनी पात्रता के अनुसार, कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी - वेतनमान - I और मध्यम प्रबंधन श्रेणी - वेतनमान - II तथा III के अधिकारी 4,500 किलोमीटर (एक तरफ की यात्रा) की दूरी तक और वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी - वेतनमान - IV और उससे अधिक के अधिकारी 5,500 किलोमीटर (एक तरफ की यात्रा) रेल यात्रा के लिए पात्र किराए के समतुल्य राशि का नकदीकरण कराने हेतु पात्र होंगे:

बशर्ते कि 1 जून 2015 से, अपनी छुट्टी यात्रा रियायत के नकदीकरण के विकल्प का चयन करने वाला अधिकारी, नकदीकरण किए जाने वाले ब्लॉक के दौरान केवल एक बार अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए दावा कर सकता है और छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा के नकदीकरण के समय छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करते समय की विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है।

(3क) एक अधिकारी जिस माध्यम और श्रेणी से सामान्यतः स्थानांतरण होने पर यात्रा करने हेतु पात्र होता है, उसी प्रकार छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठा सकता है और अधिकारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने से संबंधित अन्य नियम व शर्तें निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय अनुसार होंगी:

बशर्ते कि 1 मई, 2010 से, कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I का अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाते हुए सबसे कम किराया इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने के लिए पात्र होगा, ऐसे मामले में वास्तविक किराया या तय की गई दूरी के लिए रेल एसी प्रथम श्रेणी का किराया, इसमें से जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति की जाएगी और 1000 किलोमीटर से कम दूरी होने पर छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने के दौरान यही नियम मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II और मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के अधिकारी पर भी लागू होंगे।"

17. उक्त विनियम की अनुसूची हेतु निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"अनुसूची"

[विनियम 23(2) देखें]

नवंबर, 2012 के पहले दिन से, एक अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए तब तक पात्र होगा जब तक कि उन्हें नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट किए अनुसार पूर्ण या आंशिक रूप से वापस लिया या संशोधित नहीं किया जाता है, अर्थात्: -

तालिका

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रू.)	
		वेतन रू.24,000 से कम	वेतन रू.24,000 से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मिजोरम क) चिंपटुईपुई जिला और लुंगलेई जिले के लुंगलेई टाउन से 25 कि.मी. से अधिक के क्षेत्र।	2000	2600
	ख) संपूर्ण लुंगलेई जिला - लुंगलेई शहर से 25 किमी से अधिक के क्षेत्रों को छोड़कर)	1600	2100
	ग) संपूर्ण आइजोल जिला	1200	1500
2.	नागालैंड	1600	2100
3.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह क) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, निकोबार और नारकोंडम द्वीप समूह	2000	2600
	ख) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	1600	2100
4.	सिक्किम	2000	2600
5.	लक्षद्वीप समूह	2000	2600
6.	असम	320	400
7.	मेघालय	320	400
8.	त्रिपुरा (क) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र	1600	2100
	(ख) पूरा त्रिपुरा - दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर।	1200	1500
9.	मणिपुर	1200	1500
10.	अरुणाचल प्रदेश (क) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र	2000	2600
	(ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश।	1600	2100

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रू.)	
		वेतन रू.24,000 से कम	वेतन रू.24,000 से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	जम्मू और कश्मीर		
	1) कठुआ जिला : नियाबत बानी, लोही, मल्हार और मछोडी	2000	2600
	2) उधमपुर जिला: (क) डूडू बसंतगढ़, लैंडर भामाग इलाका, भाग 2 (ख) में शामिल लोगों के अलावा।	2000	2600
	(ख) कम्बन साइड से गोएल तक के क्षेत्र और मोहरे तहसील में किआसी साइड से अरनस तक के क्षेत्र ।	1600	2100
	(3) डोडा जिला: किश्तवाड़ तहसील में पाडर और नियाबत नौगाम के इलाके	2000	2600
	4) लेह जिला: जिले के सभी स्थान	2000	2600
	5) बारामूला जिला (क) संपूर्ण गुरेज-निरबत, तांगदार उप-मंडल और केरान इलाका	2000	2600
	(ख) माछिल	1600	2100
	(6) पुंछ और राजौरी जिला: पुंछ और राजौरी जिले के क्षेत्र, दो जिलों में पुंछ और राजौरी और सुंदरबनी और अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर	1200	1500
	(7) क्षेत्र जो ऊपर (1) से (6) तक में शामिल नहीं हैं, लेकिन जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से या वे स्थान जिन्हें राज्य सरकार ने अपने स्वयं के कर्मचारियों हेतु समय-समय पर सीमा भत्ता के लिए अर्हक घोषित किया जाता है, से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर हैं।	1200	1500
12.	हिमाचल प्रदेश		
	(1) चंबा जिला (क) पांगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायत: बड़गांव, बाजोल, देओल कुगती, नयागाम और टुंडा, गांव: ग्राम पंचायत जगत का घाटू, ग्राम पंचायत चौहटा का कनारसी	2000	2600
	(ख) भरमौर तहसील, उपरोक्त (क) में शामिल पंचायतों और गांवों को छोड़कर।	1600	2100
	(ग) भटियात तहसील में झंडरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी टाउन (मुख्य बानीखेत सहित)	1200	1500

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रू.)	
		वेतन रू.24,000 से कम	वेतन रू.24,000 से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)
	(2) किन्नौर जिला: (क) असरंग, चितकुल और हांगो कुनो / चरण पंचायत, 15/20 क्षेत्र जिसमें ऊपर निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर छोटा खंबा, नाथपा और रूपी, पूह उप-मंडल की ग्राम पंचायतें शामिल हैं।	2000	2600
	(ख) उपरोक्त (क) में शामिल क्षेत्रों के अलावा पूरा जिला।	1600	2100
	(3) कुल्लू जिला: (क) निरमंड तहसील के 15/20 क्षेत्र, जिसमें खरगा, कुशवार और सरगा की ग्राम पंचायतें शामिल हैं	2000	2600
	(ख) बाहरी-सराज (निरमंड तहसील में बुरो और जकात-खाना के गांव छोड़कर) तथा बाहरी सराज क्षेत्र और पंडरबीस के परगना को छोड़कर पूरा जिला, किंतु निरमंड तहसील के जगत-खाना और बुरो गांव सहित।	1200	1500
	(4) लाहौल और स्पीति जिला: लाहौल और स्पीति का पूरा क्षेत्र	2000	2600
	(5) शिमला जिला: (क) रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदना, सरपारा और चडी-बरांडा की पंचायतें शामिल हैं।	2000	2600
	(ख) डोरा-कवार तहसील, रामपुर में डारकली की ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील और परगना सराहन की मुनीश, गोरी चाईबीस।	1600	2100
	(ग) परगना सराहन की चौपाल तहसील और घोरी, पंजगांव, पटसनौ, नौबिस और तीन कोटी, तकलेश क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत, रामपुर तहसील के परगना रामपुर की परगना बाराबीस, कस्बा रामपुर और घोरी नोग, शिमला टाउन और उसके उपनगर (ढल्ली, जाटोग, कसुमटी, मशोबरा, तारादेवी और टूटू)।	1200	1500
	(6) कांगड़ा जिला: (क) बड़ा भांगल और छोटा भांगल के क्षेत्र	1600	2100
	(ख) कांगड़ा जिले का धर्मशाला टाउन और नगरपालिका सीमा के बाहर के निम्नलिखित कार्यालय, लेकिन धर्मशाला टाउन में शामिल हैं - महिला आईटीआई, दारी, मैकेनिकल वर्कशॉप, रामनगर, बाल कल्याण और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिस, सकोह, सीआरएसएफ ऑफिस लोअर	1200	1500

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रू.)	
		वेतन रू.24,000 से कम	वेतन रू.24,000 से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)
	सकोह, कांगडा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगियार, एचआरटीसी कार्यशाला, सदर, क्षेत्रीय मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्टरी, दारी, आईपीएच उप-मंडल, दान, बंदोबस्त कार्यालय, शामनगर, हिनवा परियोजना, शामनगर, कांगडा जिले का पालमपुर टाउन, पालमपुर में एचपीकेवीवी कैंपस सहित और निम्नलिखित कार्यालय जो इसकी नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित हैं, लेकिन पालमपुर टाउन में शामिल हैं - एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय परिसर, पशु विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बनुरी, रेशम उत्पादन कार्यालय/भारत-जर्मन कृषि कार्यशाला/एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुंदला, विद्युत उप-मंडल, लोहना, डी.पी.ओ. निगम, बुंदला, इलेक्ट्रिकल एचईएसईई डिवीजन, घुग्गर।		
	(7) मंडी जिला: जोगिन्दरनगर तहसील की छुहार घाटी, थुनाग तहसील की पंचायतें - बगरा, छतरी, छोटधार, गरागुशैन, गट्टू, गरियास, जंजैहली, जरयार, जोहर, कल्हानी, कलवान, खोलानल, लोठ, सिलीबागी, सोमाचन, तछधार, ताची, थाना, पंचायतें धरमपुर प्रखंड-बिंगा, कमला, सकलाना, तान्यार और तारखोला, करसोग तहसील की पंचायतें-बालिधर, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, महूदी, मांज, पेखी, सैज, सराहन और तेबन, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें-बोही, बटवारा, धनयारा, पौरा-कोठी, सेरी और शोजा।	1200	1500
	(8) सिरमौर जिला: बानी, बखाली (पाछड़ तहसील), भारोग भनेरी (पोंटा तहसील), बिड़ला (नाहन तहसील), डिब्बर (पाछड़ तहसील) और थाना कसोगा (नाहन तहसील) और थांसगिरी ट्रैक्ट की पंचायतें	1200	1500
	(9) सोलन जिला: मंगल पंचायत।	1200	1500
	(10) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (9) में शामिल नहीं हैं।	320	400
13.	उत्तर प्रदेश : चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	2000	2600

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रू.)	
		वेतन रू.24,000 से कम	वेतन रू.24,000 से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	उत्तराखंड: चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	2000	2600

विवरणात्मक ज्ञापन

इन विनियमों में दिए गए पूर्वव्यापी प्रभाव बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारियों के वेतन और अन्य भत्तों और लाभों से संबंधित हैं और अनिवार्य रूप से हितकारी विधान हैं। इसलिए, इन विनियमों के उक्त प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से इस तरह के पूर्वव्यापी आवेदन के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राधे श्याम बंसल, महाप्रबंधक, (मानव संसाधन प्रबंध)

[विज्ञापन-III/4/असा./510/2021-22]

फुट नोट:- यह संशोधन विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रकाशित किए गए, अर्थात् :-

क्रमांक	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना दिनांक	दिनांक, जब राजपत्र में प्रकाशित हुई
1.	-----	7.12.1987	26.12.1987
2.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/14046/96	5.5.1997	17.5.1997
3.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर /3169/2001	19.5.2001	16.6.2001
4.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर /853/2003	11.2.2003	15.3.2003
5.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर /2053/2006	21.3.2006	7.4.2006
6.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर /5207/2006	30.5.2008	5.6.2008
7.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/1324/2017-18	1.3.2008	14.03.2018

BANK OF MAHARASHTRA

(HEAD OFFICE: PUNE)

NOTIFICATION

Pune, the 7th December, 2021

F. No AX1/ST/OSR/1325/2021-22.—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Bank of Maharashtra after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bank of Maharashtra (Officers') Service Regulations, 1979, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Bank of Maharashtra (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2021.
- (2) Save as provided in these regulations, they shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2012.
2. In the Bank of Maharashtra (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely : —

‘(f) “family” means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), wholly dependent physically and mentally challenged brother or sister with forty per cent. or more disability, widowed daughters and dependent divorced or separated daughters, sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters, and parents wholly dependent on the officer and in the case of a married female officer may include her natural parents or parents-in-law, but not both.

Explanation. — “wholly dependent” shall mean such member of the family having an income not exceeding Rs.10,000 per month and where the wholly dependent family members are parents, the income of any parent or aggregate income of both the parents if exceeds Rs.10,000 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer;’.

3. In regulation 4 of the said regulations, for sub-regulation (6), the following sub-regulations shall be inserted, namely: —

“[6] With effect from the 1st day of November, 2012, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

(a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.76520 – 2120/4 – 85000

Scale VI = Rs.68680 – 1960/4 – 76520

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.59170 – 1650/2 – 62470 – 1800/2 – 66070

Scale IV = Rs.50030 – 1460/4 – 55870 – 1650/2 – 59170

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.42020 – 1310/5 – 48570 – 1460/2 – 51490

Scale II = Rs.31705 – 1145/1 – 32850 – 1310/10 – 45950

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.23700 – 980/7 – 30560 – 1145/2 – 32850 – 1310/7 – 42020

Explanation. — Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on the 31st October, 2012 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st November, 2012 on stage-to-stage basis, or the corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual.

(7) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4), (5) and (6) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(8) With effect from 1st day of November, 2012, officers shall be paid Special Allowance as under:

Scale I-III = 7.75% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV-V = 10% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI-VII = 11% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Note: The Special Allowance referred to in sub-regulations (8) with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including New Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.”.

4. In regulation 5 of the said regulations, —

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: —

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (6) of regulation 4, on and from the 1st day of November, 2012, the increments shall be granted subject to the following, namely: —

(a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (6) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) one year after reaching the maximum in their respective Scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher Scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar;

(c) Officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher scale, shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which the first two shall be Rs. 1310 each and next two Rs.1460 each;

(d) Officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b) after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.1460 each for every three completed years of service and a fourth stagnation increment of Rs.1460 two years after receipt of third stagnation increment:

Provided that officers who have completed two years or more after receipt of the third stagnation increment shall be granted the fourth stagnation increment with effect from 1st day of May,2015;

(e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III (those recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III) shall be eligible for three stagnation increments of Rs.1460 each for every three completed years of service and fourth stagnation increment of Rs.1460 to officers who have completed two years or more after releasing third stagnation increment as on 1st May,2015 and a fifth stagnation increment of Rs.1460 two years after receipt of fourth stagnation increment provided that the officers who have completed two years after receipt of the fourth stagnation increment shall be granted the fifth stagnation increment with effect from 1st May, 2015;

(f) officers in Senior Management Grade Scale-IV shall be eligible for one stagnation increment of Rs.1650 three years after reaching the maximum of scale with effect from 1st May, 2015;

Provided that such increment shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation.— Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.”;

(ii) in sub-regulation(2), in the Explanation, after clause (f) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:—

“(g) On and from the 1st day of November, 2012, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below:

TABLE

(1)	(2)
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers – Part I	Rs. 670 per month, one year after reaching maximum of the scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs. 670 per month, one year after reaching maximum of the scale. (ii) Rs.1680 per month, two years after reaching maximum of the scale:

Provided that an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay shall be granted from the date of acquiring such qualification, the first instalment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent instalments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first instalment of Professional Qualification Pay”;

(iii) in sub-regulation (3), after the table under clause (e), the following shall be inserted, namely:—

“(f)” on and from the 1st November, 2012, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2012 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank’s accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1310	143	1453
1460	159	1619
1650	180	1830
1800	196	1996
1960	214	2174
2120	231	2351

Note:

(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under Column (3) of the tables in clauses (b), (c), (d), (e) and (f) of this sub-regulation shall be payable to those officer who are provided with Bank’s accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the table under clause (f) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2), (3), (4), (5) and (6) of regulation 4 is earned.

(iii) Only Officers who were in the service of the bank on or before 1st November, 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay they are placed.

(iv) On and from the 1st November, 1999, there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) under sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any instalment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from that date and second instalment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1st November, 2000.

- (v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.
- (vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) of this sub-regulation shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e) or (f) above, one year after reaching the maximum of the scale.”.
5. In regulation 21 of the said regulations, after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely: —

“(6) On and from the 1st day of November, 2012, Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.10% of Pay.

Explanation. – For the purposes of this sub-regulation, —

- (a) “pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments plus Special Allowance;
- (b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in clauses (c), (d), (e), (f) and (g) to the explanation in sub-regulation (2) of Regulation 5 shall rank for Dearness Allowance.”.
6. In regulation 22 of the said regulations, —

- (i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: —

“(1) on and from the 1st day of November, 2012, —

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:—

TABLE

Place of work	House Rent Allowance
(1)	(2)
(i) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	9.0 per cent of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	8.0 per cent of Pay
(iii) Other places	7.0 per cent of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in Column (2) of the above table.

Note:- The claims of officer for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.”.

7. In regulation 23 of the said regulations, —

(A) for sub-regulations (1), (2), (3), (4), and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st day of November, 2012, if an Officer is serving in a place mentioned in column (1) of the table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column (2) thereof against that place shall be payable: —

TABLE

Places	Rates
(1)	(2)
(i) Places in Area 1 and in the State of Goa	4 per cent of basic pay subject to a maximum of Rs.870 per month
(ii) Places with population of five lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair.	3 per cent of basic pay subject to a maximum of Rs.600 per month.

(2) On and from 1st day of November, 2012, the rates of Special Areas Allowance shall be as specified in the Schedule to these Regulations.

(3) On and from the 1st day of November, 2012, if an officer is serving in an area specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.400 per month or Rs.350 per month according to the classification of area as Group A or Group B respectively.

(4) On and from 1st day of June, 2015, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.1100 per month from the date he reports to the latter place up to the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st day of June, 2015, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs.4000 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.2000 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.2000 per month.”;

(B) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely: —

“(8)” On and from 1st day of November, 2012, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.200 per month.”;

(C) in sub-regulation (10),—

(a) for the figures, letters and words “1st day of November 2007”, the figures, letters and words “1st day of November, 2012” shall be substituted;

(b) For the table, the following table shall be substituted, namely:—

“TABLE

Place	Rate
(1)	(2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2 per cent of pay subject to a maximum of Rs.750 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5 per cent of pay subject to a maximum of Rs.1000 per month

(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5 per cent of pay subject to a maximum of Rs.2000 per month
---	---

8. In regulation 24 of the said regulations,—

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(1)” On and from 1st day of November, 2012, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amount claimed as specified in the table below, namely:—

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
(1)	(2)
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.8000 per annum or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.9050 per annum or the amount incurred whichever is less

Note:

(i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above; or

(ii) for the year 2012, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November, 2012 and December, 2012.

(1A) An officer shall be eligible for medical insurance facility for self and his family, as per the terms and conditions specified by the Board.”.

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2012, a sum equal to 0.75 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.15 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

10. In regulation 33 of the said regulations for sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(4) On and from 1st day of June 2015, Privilege Leave may be accumulated up to not more than two hundred and seventy days except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that encashment of Privilege Leave shall be restricted up to a maximum of two hundred and forty days:

Provided further that an officer desiring to avail of Privilege Leave shall ordinarily give not less than fifteen days’ notice of his intention to avail of such leave.”.

11. In regulation 34 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(4) On and from the 1st June 2015, Special Sick Leave up to thirty days may be granted to an officer once during his entire period of service for donation of kidney or organ.”.

12. In regulation 36 of the said regulations for sub-regulation (2) and (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) With effect from the 25th May 2015, leave may also be granted once during service to a childless female officer for legally adopting a child who is below one year of age for a maximum period of six months subject to the following terms and conditions:—

- (i) leave will be granted for adoption of only one child;
- (ii) the adoption of a child shall be through a proper legal process and the officer shall produce the adoption deed to the Bank for sanctioning such leave;
- (iii) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy; and
- (iv) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service.

(3) With effect from the 25th day May, 2015, within the overall period of twelve months, leave may also be granted in case of hysterectomy up to a maximum of sixty days.

(4) Maternity leave, which shall be on substantive pay, shall be granted to a female officer for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that within the overall period of twelve months, leave may also be granted in case of miscarriage or abortion or Medical Termination of Pregnancy.

(5) With effect from 1st June 2015, male officer employees having up to two surviving children shall be eligible for fifteen days paternity leave during his wife’s confinement which may be combined with any other kind of leave except casual leave:

Provided that the leave shall be applied up to fifteen days before or up to six months from the date of delivery of the child.”

13. For regulation 38 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

“38. Lapse of Leave, — Save as provided below, all leave to the credit of an officer shall lapse on resignation, retirement, death, discharge, dismissal or termination:

Provided that where an officer retires from the bank’s service, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period, not exceeding two hundred and forty days of privilege leave that he had accumulated:

Provided further that where an officer has been compulsorily retired including as a measure of punishment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to emoluments of any period, not exceeding two hundred and forty days of privilege leave that he has accumulated:

Provided also that where an officer dies while in service, there shall be payable to his legal representatives, a sum equivalent to the emoluments for the period not exceeding two hundred and forty days of privilege leave to his credit as on the date of his death:

Provided also that where an officer resigns from service on or after 1st April, 2001 after giving due notice as in sub-regulation (2) of regulation 20, he may be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of privilege leave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service, subject to a maximum of one hundred and twenty days.”

14. In regulation 41 of the said regulation,—

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from 1st day of November 2012, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely:—

- (a) an officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1st class or AC 2- tier sleeper by train:

Provided that he may travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

- (b) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st class or AC 2-tier sleeper by train:

Provided that he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 Kilometres:

Provided further that he may travel by air (economy class) even for shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

- (c) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st class by train or by air (economy class);
- (d) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 Kilometers:

Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car;

- (e) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the bank's vehicle;
- (f) an officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail.”;
- (ii) in sub-regulation (4), for clauses (a), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(a) On and from the 1st June, 2015, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the table below shall be entitled to per diem Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:—

TABLE

Grade/Scales of Officers	Metro (Rs.)	Major 'A' Class Cities (Rs.)	Area-1 (Rs.)	Other Places (Rs.)
(1)	(2)			
Officers in Scale VI and above	1800	1300	1100	950
Officers in Scale IV and V	1500	1300	1100	950
Officers in Scale I, II and III	1300	1100	950	800

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, halting allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation. — For the purpose of computing halting allowance, “per diem” shall mean each period of twenty four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the schedule time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours.”.

15. In regulation 42 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub – regulation shall be substituted, namely:—

“(3) On and from the 1st day of June, 2015 an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc.’ as specified in the table below, namely:—

TABLE

Grade or Scale	Amount
(1)	(2)
Top Executive and Senior Management Grade (Officers in Scale IV and above)	Rs. 20,000
Middle Management and Junior Management Grade (Officers upto Scale III)	Rs. 15,000"

16. In regulation 44 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub- regulation shall be substituted, namely: —

“(3) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that, he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route:

Provided further that with effect from 1st June 2015, alternatively, an officer, by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case may be, surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 4,500 Kilometers (one way) for officers in JMG-Scale-I and MMG – Scale II and III and 5,500 Kilometers (one way) for officers in SMG - Scale IV and above:

Provided also that with effect from 1st June 2015, an officer opting to encash his Leave Travel Concession, shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3A) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from 1st May, 2010 an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by train for the distance travelled whichever is less and the same rules shall apply when an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 Kilometres.”.

17. For the schedule to the said regulation, the following schedule shall be substituted, namely: —

“SCHEDULE”

[See regulation 23(2)]

With effect from the 1st day of November, 2012, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the table below, namely:—

TABLE

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below ₹24,000	Pay above ₹24,000
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mizoram		
	a) Chimpluipui District and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District.	2000	2600
	b) Entire Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town.	1600	2100
	c) Entire Aizawl District	1200	1500
2.	Nagaland	1600	2100

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below ₹24,000	Pay above ₹24,000
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600
	b) South Andaman (including Port Blair)	1600	2100
4.	Sikkim	2000	2600
5.	Lakshadweep Islands	2000	2600
6.	Assam	320	400
7.	Meghalaya	320	400
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	1600	2100
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500
9.	Manipur	1200	1500
10.	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2600
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100
11.	Jammu and Kashmir		
	1) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	2) Udhampur District: (a) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b).	2000	2600
	(b) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1600	2100
	(3) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	(4) Leh District : All places in the District	2000	2600
	(5) Barmulla District (a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqua	2000	2600
	(b) Matchill	1600	2100
	(6) Poonch and Rajouri District : Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts	1200	1500
	(7) Areas not included in (1) to (6) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	1200	1500
12.	Himachal Pradesh		
	(1) Chamba District (a) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	2000	2600
	(b) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in (a) above.	1600	2100
	(c) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below ₹24,000	Pay above ₹24,000
(1)	(2)	(3)	(4)
	(2) Kinnaur District: (a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/ Charang Panchayats, 15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Ruppi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	2000	2600
	(b) Entire District other than Areas included in (a) above.	1600	2100
	(3) Kullu District: (a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	2000	2600
	(b) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	(4) Lahaul and Spiti District : Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	(5) Shimla District : (a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	2000	2600
	(b) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan.	1600	2100
	(c) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1200	1500
	(6) Kangra District: (a) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	1600	2100
	(b) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiari, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidhalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	1200	1500
	(7) Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri	1200	1500

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below ₹24,000	Pay above ₹24,000
(1)	(2)	(3)	(4)
	and Shoja.		
	(8) Sirmaur District: Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), Bharog Bheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract	1200	1500
	(9) Solan District : Mangal Panchayat.	1200	1500
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.	320	400
13.	Uttar Pradesh: Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts	2000	2600
14.	Uttarakhand: Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts	2000	2600

EXPLANATORY MEMORANDUM

The retrospective effect given in these regulations relate to the pay and other allowances and benefits to the officers of the Bank of Maharashtra and are essentially beneficial legislation. Hence, giving retrospective effect to the said provisions of these regulations will not adversely affect the interest of any person as a result of such retrospective application.

RADHEY SHYAM BANSAL, GM, (Human Resources Management)

[ADVT.-III/4/Exty./510/2021-22]

Foot note: The amendment regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, vide the following notifications, namely: –

Serial number	Notification number	Notification date	Date on which published in Official Gazette
1.	-----	7.12.1987	26.12.1987
2.	AX-1/ST/OSR/14046/96	5.5.1997	17.5.1997
3.	AX-1/ST/OSR/3169/2001	19.5.2001	16.6.2001
4.	AX-1/ST/OSR/853/2003	11.2.2003	15.3.2003
5.	AX-1/ST/OSR/2053/2006	21.3.2006	7.4.2006
6.	AX-1/ST/OSR/5207/2006	30.5.2008	5.6.2008
7.	AX-1/ST/OSR/1324/2017-18	1.3.2008	14.03.2018